

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) बड़ी और मीटर लाइन पर लम्बी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों पर कंडक्टरों की व्यवस्था है।

(ख) अजमेर-रतलाम खण्ड की गाड़ियों पर कंडक्टरों की व्यवस्था करने का प्रोचिन्त्य नहीं पाया गया है।

रतलाम और कोटा डिवीजनों  
(पश्चिम रेलवे) में कंडक्टर

265. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम और कोटा डिवीजनों के कंडक्टरों के पदों सम्बन्धी विवाद विचाराधीन हैं;

(ख) क्या इसके कारण रतलाम डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के लगभग 30 कंडक्टरों की पदोन्नति रुकी हुई है; और

(ग) यदि हा, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). विभिन्न मण्डलों में कंडक्टरों के पदों के वितरण से सम्बन्धित आदेशों को कुछ कर्मचारियों ने न्यायालय में चुनौती दी है और न्यायालय ने अन्तरिम निवेधाज्ञा जारी कर दी है। निवेधाज्ञा के उठा लिए जाने तक पहले से चालू व्यवस्था जारी रखी जा रही है।

नर्मदा जल विवाद

266. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री प्रभु दास पटेल :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद पर विचार करने के लिए गत जून में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हा, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बंजनाथ कुरील) : (क) और (ख) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अधिकारियों की एक बैठक 20 और 21 जून, 1972 को हुई थी।

इसके पश्चात् 18 से 22 जुलाई, 1972 तक सिंचाई और विद्युत् मंत्री ने गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया। मुख्य मंत्रियों ने कहा कि यद्यपि नर्मदा देश की सर्वोत्तम नदियों में से एक है और इसकी विपुल शक्ति है, इसका अभी तक बिकास नहीं किया गया है। उन्होंने भारत सरकार से अनुरोध किया कि दशाब्दी में इसके विकास को प्राथमिकता प्रदान की जाए। मुख्य मंत्रियों ने महसूस किया कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों में नर्मदा के बिकास में और अधिक देर नहीं करनी चाहिए और इसलिए वे इस नदी से संबंधित विवादों को आपसी समझौते द्वारा और प्रधान मंत्री की सहायता से तय करने के लिए सहमत हो गए।

वर्षों के 75 प्रतिशत के लिए नर्मदा में उपलब्ध जल की मात्रा लगभग 28 मिलियन एकड़ फुट बांकी गयी है। महाराष्ट्र और राजस्थान की उनके अपने क्षेत्रों में उपयोग के लिए जल आवश्यकता क्रमशः 0.25 और 0.5 मिलियन एकड़ फुट है, ये आवश्यकताएं बिना नहर के स्तर का ख्याल किए बांकी गई है।